आधी आबादी

हर सन्डे वूमेन्स डे

संस्करण – रविवार, 07 अप्रैल 2024, अंक – 48

बुजुर्गों को पेंशन, महिलाओं को नौकरी, मंत्रालयों में कटौती... मोदी 3.0 में इन बातों पर होगा फोकस

चुनाव की सरगर्मियाँ जोरों पर हैं। आए दिन किसी न किसी मुद्दे पर वाद-विवाद और बवाल जारी है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी लगातार कह रहे हैं कि उन्हें तीसरा कार्यकाल मिलना निश्चित है। पीएम मोदी के अनुसार वह जमीनी स्तर पर काम करना चाहते हैं। ऐसे में शीर्ष सरकारी अधिकारी नई व्यवस्था के लिए एक कार्य योजना तैयार कर रहे हैं। इसमें बुजुर्गों के पेंशन का दायरा बढ़ाने, मंत्रालयों की संख्या में कटौती, भारतीय मिशन की संख्या में बढ़ोतरी, ई-वाहनों की बिक्री बढ़ाने समेत अन्य बातों पर फोकस रहेगा। कार्ययोजना के अनुसार अगले छह वर्षों में भारतीय मिशनों की संख्या को 20% बढ़ाकर 150 करना, बुनियादी ढांचे में अधिक निजी निवेश और प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए एक तंत्र विकसित करना शामिल है।

■ हीरेंद्र झा

वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी

इस महीने कैबिनेट सचिव द्वारा बुलाई गई बैठकों के दौरान चर्चा किए जाने वाले एक मसौदा पत्र में 2030 तक पेंशन लाभ वाले वरिष्ठ नागरिकों की हिस्सेदारी को 22% से दोगुना से अधिक बढ़ाकर 50% करने का प्रस्ताव है। महिलाओं की वर्कफोर्स में भागीदारी को 37% से बढ़ाकर 50% करना है, जो वर्तमान वैश्विक औसत 47% से अधिक है। ई-वाहनों पर जोर वाहन बिक्री में उनकी हिस्सेदारी को 7% से बढ़ाकर 30% से अधिक करने के लक्ष्य से स्पष्ट है।

जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र की हिस्सेदारी

आर्थिक मोर्चे पर, लक्ष्य ऑटोमोबाइल, कपड़ा, फार्मा, पर्यटन और सेवाओं जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने और विनिर्माण और निर्यात की हिस्सेदारी बढ़ाने की ओर इशारा करते हैं। 2030 तक औद्योगिक क्षेत्र का जीडीपी में योगदान को 28% से बढ़ाकर 32.5% करने का लक्ष्य है। हालांकि इनमें से कई मुद्दों पर अतीत में भी चर्चा की गई है, चुनाव घोषणा से पहले पीएम के साथ चर्चा ने उन्हें फिर से एजेंडे में डाल दिया है। उदाहरण के लिए, सचिवों और मंत्रालयों के साथ अपनी बैठक के दौरान, सिविल सेवकों ने परिवहन क्षेत्र के मंत्रालयों के बीच एकीकरण का आह्वान किया था।

इन बातों पर रहेगा फोकस

दुनियाभर में भारतीय मिशनों की संख्या को 20% बढ़ाकर 150 करना, वर्तमान में 54 मंत्रालयों की संख्या में कमी पर विचार, बुनियादी ढांचे में अधिक निजी निवेश और प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए एक तंत्र विकसित करना, 2030 तक पेंशन लाभ वाले वरिष्ठ नागरिकों की हिस्सेदारी बढ़ाकर 50% करना, ई-वाहनों की हिस्सेदारी 7% से बढ़ाकर 30% से अधिक करने का लक्ष्य, 2030 तक अदालतों में लंबित मामलों को 5 करोड़ से घटाकर 1 करोड़ से कम करना, निचली न्यायिक प्रणाली में मामलों के निपटान के समय को 2,184 दिनों से घटाकर 1,000 दिन करना, अगले छह वर्षों में न्यायपालिका में रिक्तियों को 22% से घटाकर 10% करने की योजना, रक्षा बजट की हिस्सेदारी को 2% से बढ़ाकर 3% करने पर भी चर्चा, 2030 तक औद्योगिक क्षेत्र का जीडीपी में योगदान को 28% से बढ़ाकर 32.5% करने का लक्ष्य।

विशेष संपादकीय

अब महिलाओं को दरकिनार करना आसान नहीं

– दिनेश के सिंह

सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस लगातार महिला मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए एक किस्म की होड़ में नजर आ रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह है कि देश के कुल 96.8 करोड़ मतदाताओं में आधी महिलायें ही हैं। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने जहां महिलाओं पर केंद्रित व्यापक स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य कार्यक्रमों की शुरुआत की है, वहीं कांग्रेस ने नारी न्याय योजना की पेशकश की है जिसके तहत महिलाओं के बैंक खातों में एक लाख रुपये डाले जाएंगे और केंद्र सरकार की सभी नौकरियों में उन्हें 50 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। ऐसे बढ़ा-चढ़ाकर किए गए वादे किस हद तक पूरे हो सकते हैं यह एक बड़ा सवाल है लेकिन यह देखना विचित्र है कि सभी दल राजनीतिक बयानबाजी में इतने आगे निकल चुके हैं। पिछले वर्ष संसद के विशेष सत्र में 106वां संशोधन अधिनियम पारित होने के बाद यह विषय खासतौर पर विवादास्पद हो गया है। इसे महिला आरक्षण विधेयक के नाम से जाना जाता है जिसके तहत 15 वर्षों तक महिलाओं को संसद में 33 फीसदी आरक्षण देने की बात कही गई है। चूंकि यह प्रावधान परिसीमन के बाद लागू होगा इसलिए सभी राजनीतिक दलों के पास पर्याप्त समय है कि वे इसके लिए अपनी चुनावी सूची तैयार कर सकें। इसके बावजूद राजनीतिक दल महिलाओं के मुद्दों पर दिखावा ही करते हैं और इसकी एक बानगी यह है कि किसी प्रमुख राजनीतिक दल ने अपनी पार्टी उम्मीदवारों की सूची में अब तक महिलाओं को समुचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। इस होड़ में भाजपा आगे है और 25 मार्च तक उसने जितने उम्मीदवार घोषित किए हैं उनमें 17 फीसदी महिलाएं हैं। अब तक 66 महिला उम्मीदवारों के साथ पार्टी ने लैंगिक आधार पर अपना प्रदर्शन सुधारा है। साल 2014 में उसके 428 उम्मीदवारों में से 38 महिलाएं थीं, 2019 में यह आंकड़ा सुधरकर 436 में से 55 हुआ। कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची बताती है कि उसने अब तक 12 फीसदी महिलाओं को टिकट दिया है। सबसे अधिक चकित करने वाली सूची तृणमूल कांग्रेस की है। पार्टी ने पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से 12 पर महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है। बहरहाल, कुल मिलाकर भले ही आंकड़े हतोत्साहित करने वाले हों लेकिन ये 2019 के आम चुनाव की तुलना में बेहतर रहने वाले हैं जब कुल प्रत्याशियों में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 9 फीसदी थी। पिछली लोक सभा में 78 महिलाएं चुन कर आई थीं जो कुल सदस्यों का 14.3 फीसदी था। इसके बावजूद यह देश के आम चुनावों के इतिहास में महिलाओं की सबसे बड़ी संख्या थी। चरणबद्ध तरीके से हो रहा स्थिर सुधार उत्साहित करने वाला है लेकिन ये आंकड़े बताते हैं कि महिला आरक्षण कानून लागू होने के बाद राजनीतिक दलों को तेजी से प्रयास करने होंगे। इंटर-पार्लियामेंटरी यूनियन (आईपीयू) के अनुसार फिलहाल भारत संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के 26.9 फीसदी के वैश्विक औसत से काफी पीछे है। आईपीयू की संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी की ताजा मासिक वैश्विक रैंकिंग में भारत 184 देशों में से 144वें स्थान पर है। कॉर्पोरेट बोर्ड में महिलाओं का प्रतिनिधित्व हालांकि कम है लेकिन इसमें सुधार हुआ है। 2019 के 15 फीसदी के बजाय अब 20 फीसदी महिलाएं कंपनियों के बोर्ड में हैं। परंतु संसद तथा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी दोगुनी करने के लिए सभी दलों को महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर खास ध्यान देना होगा।

इंटरव्यू

मोदी हमारे लिए देवतुल्य हैं : कंगना रनौत

“भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली हिमाचल की पहली महिला उम्मीदवार कंगना रनौत के साथ मंडी के मुख्य संवाददाता हंसराज सैनी ने कई विषयों पर बातचीत की, जो आप यहाँ पढ़ सकते हैं।”

सवाल: अक्सर यह कहा जाता है कि कंगना रनौत गुस्से में बात करती हैं?

कंगना: मैं कभी गुस्सा नहीं करती हूं। हां, मैं सच का साथ देती हूं। सत्य को मैं पूरी ताकत के साथ रखती हूं और सभी जानते हैं कि सत्य हमेशा कड़वा होता है।

सवाल: आपका टिकट तय होने के बाद अशोभनीय टिप्पणी हुई। आपदा में गायब होने के आरोप पर क्या कहेंगी?

कंगना: कांग्रेस की मानसिकता महिला विरोधी रही है, परंतु कांग्रेस की महिला नेता की टिप्पणी ज्यादा पीड़ादायक इसलिए है कि उन्होंने एक महिला होकर मेरा ही अपमान नहीं किया, देवभूमि की लाखों महिलाओं का भाव लगाकर उनके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचाई। यह टिप्पणी केवल सुप्रिया श्रीनेत की नहीं है, यह कांग्रेस की मानसिकता है। जितना संभव था, मैंने भी किया। मुझ पर प्रश्नचिह्न खड़े करना कांग्रेसी युवराज की कुंठा और चुनावी दबाव है और कुछ नहीं।

सवाल: चुनाव के लिए मंडी ही क्यों चुना?

कंगना: आज देश सबसे बेहतरीन दौर से गुजर रहा है। लोग एक परिवार की राजनीति से बाहर निकल कर विकास की राजनीति पर विश्वास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पास विजन है और बिना लालच, बिना थके, बिना स्वार्थ राष्ट्र निर्माण का संकल्प सच्चे मन से कर रहे हैं तो कोई भी विरोधी ताकत आपको नहीं रोक सकती। मोदी जी की इसी विशेषता से प्रेरित होकर राजनीति में आई हूं। मैं मंडी में पैदा हुई हूं। मेरी जन्मभूमि मंडी है। इसीलिए मंडी से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। मेरे परदादा भी मंडी जिले से ही कांग्रेस के विधायक रहे, क्योंकि उन दिनों और दल था ही नहीं। यदि वह अब होते तो भाजपा में ही होते, क्योंकि भाजपा ही विकास की बात करती है, अन्य दल परिवार की।

सवाल: अक्सर देखा गया है कि स्टारों के राजनीति में अनुभव अच्छे नहीं रहे हैं। क्या आपको ढूंढने मुंबई जाना पड़ेगा?

कंगना: मैं मातृभूमि से चुनाव लड़ रही हूं। मंडी संसदीय क्षेत्र के हक व विकास के लिए आप कंगना को अपने बीच पाएंगे। कंगना और मंडी संसदीय क्षेत्र को अब कोई अलग नहीं कर सकता। कांग्रेसी भाइयों को यह प्रश्न सोनिया गांधी जी से भी पूछना चाहिए जो अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में अंतिम बार जनवरी 2020 में गई हैं। वहां पर गांधी परिवार के खिलाफ भारी रोष है। यही कारण है कि अमेठी के बाद अब गांधी परिवार रायबरेली से भी पलायन कर चुका है।

सवाल: आप पीएम मोदी को भगवान राम और विष्णु का अवतार बता रही हैं, क्यों?

कंगना: कांग्रेस के नेता अटल बिहारी वाजपेयी के उस बयान का बार-बार उल्लेख करते हैं कि उन्होंने इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा था। कहा गया है कि हर मनुष्य में देव तत्त्व होता है, जिसमें भगवान के अंश अधिक होते हैं, उसका प्रभाव दिखता है और उसकी हर ओर जीत होती है। जो व्यक्ति मानवता, राष्ट्र और केवल मात्र जन सेवा में बिना थके कार्य कर रहा है, वह हमारे लिए देवतुल्य ही है।

हलचल

लोकसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग से पहले ममता बनर्जी का बयान, कहा- 'दंगा मत करो, दंगा मत करने दो'!

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान बड़ा बयान दिया है। ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल में किसी भी तरह से धार्मिक हिंसा को रोकने की बात कही है। ममता ने कहा कि पहले दौर के मतदान की तारीख 19 अप्रैल है? वोटिंग के पहले अन्नपूर्णा पूजा और रामनवमी है। इस दौरान राज्य में कहीं भी दंगा नहीं होना चाहिए। ममता बनर्जी ने यह बातें अलीपुरद्वार की सभा में कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि धार्मिक हिंसा फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल पिछले साल बंगाल में रामनवमी के दौरान हिंसा की कई घटनाएं सामने आई थीं। ममता बनर्जी ने शुक्रवार को अलीपुरद्वार लोकसभा सीट में चुनाव प्रचार कर रहीं थीं। वहां से उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है कि मैं सबके लिए थी, हूं और रहूंगी। इसके बाद उन्होंने बैठक में मौजूद कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी तरह की धार्मिक हिंसा न फैलने दें। उन्होंने इस बारे में कुछ टिप्पणियां कीं कि लोकसभा चुनाव का पहला चरण 19 तारीख को क्यों रखा गया है। ममता ने कहा कि अन्नपूर्णा पूजा 15 तारीख को है। हम सब करते हैं। अन्नपूर्णा मां ने किसी को भी धार्मिक हिंसा फैलाने के लिए नहीं कहा। 16 को अष्टमी है। 17 तारीख को रामनवमी है। मतदान से पहले धार्मिक हिंसा नहीं होनी चाहिए।

वायनाड से राहुल गांधी ने किया नामांकन, बहन प्रियंका गांधी के साथ किया रोड शो

लोकसभा चुनाव 2024 के लिए केरल के वायनाड से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपना नामांकन कर दिया है। इससे पहले उन्होंने एक रोड शो किया जिसमें उनके साथ कांग्रेस महासचिव और उनकी बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव में वायनाड सीट चार लाख से अधिक वोटों के भारी अंतर से जीती थी। पार्टी ने कहा कि राहुल गांधी वायनाड के एक गांव मुप्पैनाद में हेलीकॉप्टर से पहुंचे और कलपेट्टा तक सड़क मार्ग से यात्रा की। कांग्रेस ने कहा कि सुबह करीब 11 बजे उन्होंने कलपेट्टा से एक रोड शो शुरू किया, जिसमें उनके साथ प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल, दीपा दास, कन्हैया कुमार और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीसन और केपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष एमएम हसन भी शामिल रहे। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा, "आपका सांसद होना मेरे लिए गर्व की बात है। मैं आप सबको अपनी छोटी बहन प्रियंका जैसा ही समझता हूं। यहां जंगली जानवर का शिकार बनते इंसान का मुद्दा बड़ा है। मेडिकल कॉलेज का मुद्दा है। मैंने सारे मुद्दे उठाए, सीएम को पत्र लिखा लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब केंद्र और केरल में हमारी सरकार होगी हम आपकी सारे मुद्दे हल करेंगे। रोड शो के बाद दाखिल किया नामांकन रोड शो में हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने राहुल गांधी के खिलाफ के. सुरेंद्रन को मैदान में उतारा है। वायनाड में लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है।

भीमा कोरेगांव केस: छह साल जेल में रहने के बाद शोमा सेन को सुप्रीम कोर्ट से मिली ज़मानत

भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद केस में छह साल से जेल में बंद शोमा कांति सेन को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिल गई है। कोर्ट ने ज़मानत देते हुए शर्त रखी है कि वह बिना स्पेशल कोर्ट को सूचित किए महाराष्ट्र से बाहर नहीं जा सकती हैं। छह जून 2018 को शोमा सेन को पुणे पुलिस ने माओवादियों से लिंक रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसी दिन रोना विल्सन को दिल्ली से और सुधीर धवले को मुंबई से, वकील सुरेंद्र गडलिंग और महेश राउत को नागपुर से गिरफ्तार किया गया था। शोमा सेन अंग्रेज़ी की प्रोफ़ेसर हैं। गिरफ्तारी के समय वो नागपुर की आरटीएम यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी डिपार्टमेंट की हेड थीं। वे महिलाओं, आदिवासियों और दलितों के अधिकारों के मुद्दों पर लिखती रही हैं। उनके लेख प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं में छपते रहे हैं। वे 'कमेटी फ़ॉर द प्रोटेक्शन ऑफ़ डेमोक्रेटिक राइट्स' की सदस्य हैं। वे मानवाधिकार के क्षेत्र में काम कर रही कई संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने 'अत्याचार की शिकार' महिला राजनीतिक बंदियों का मामला उठाया है और उन्हें कानूनी सहायता दी है। कोर्ट ने छह साल लंबे उनके कारावास को ध्यान में रखा और साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखते हुए ज़मानत दी कि इस मामले में अब तक ट्रायल शुरू नहीं हो सका है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने शोमा सेन की ज़मानत का विरोध नहीं किया। कोर्ट ने एनआईए से पूछा था कि शोमा सेन की हिरासत क्यों जारी रहनी चाहिए? इसके जवाब में 15 मार्च को एनआईए ने कहा था कि "शोमा सेन की गिरफ्तारी अब ज़रूरी नहीं है।"

कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी किया घोषणापत्र, आधी आबादी पर विशेष ध्यान

लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने इस घोषणापत्र को 'न्यायपत्र' नाम दिया है। इस घोषणापत्र में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए 50 फ़ीसदी आरक्षण की निर्धारित सीमा को बढ़ाने की बात कही गई है। इसके लिए संविधान संशोधन लाने का भी वादा किया गया है। कांग्रेस की सरकार बनने पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए क़ानूनी गारंटी देने का वादा भी किया गया है। कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में इस घोषणापत्र को जारी किया गया। घोषणा पत्र में आधी आबादी यानी महिलाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। घोषणापत्र के मुताबिक महालक्ष्मी योजना शुरू कर हर गरीब परिवार को बिना शर्त एक लाख रुपये हर साल दिए जाएंगे, ये राशि घर की महिला को दी जाएगी। 2025 से महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की आधी नौकरियां आरक्षित की जाएंगी, फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं जैसे आशा, आंगनवाड़ी, मिड-डे मील रसोइया के वेतन में केंद्र सरकार का योगदान दोगुना किया जाएगा, मनरेगा के तहत मज़दूरी बढ़ाकर 400 रुपये प्रतिदिन की जाएगी, प्रतिदिन 400 रुपये न्यूनतम राष्ट्रीय वेतन की गारंटी देने का वादा किया गया है। इसके अलावा डिजिटल लर्निंग के महत्व को समझते हुए क्लास 9 से क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स जिनमें लड़कियां भी शमैल हैं उन्हें फोन मुहैया कराया जाएगा। 21 साल से कम उम्र के उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए 10 हज़ार रुपये प्रतिमाह की योजना शुरू होगी, जिनमें महिला खिलाड़ी भी शामिल है।

सास-बहू के सीरियल और सियासत में फर्क', महिला नेताओं को स्मृति ईरानी की सलाह

केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगर वे चाहती हैं कि राजनीति में हमें गंभीरता से लिया जाए तो महिलाओं को अहम राजनीतिक मुद्दों पर ध्यान देना होगा। सास-बहू के सीरियल, जीवन की वास्तविकताओं से बहुत दूर हैं इसलिए महिलाओं को सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सफल होने के लिए इसे समझना होगा। स्मृति ईरानी ने कहा कि वोट डालना एक भारी जिम्मेदारी है, यह है किसी टीवी सीरियल का खेल नहीं है। बेंगलुरु में कारोबारियों से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ने तस्वीरें खिंचवाकर और मुस्कुराकर देश को लूटा। स्मृति ईरानी, अमेठी लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने इस सीट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हराया था। वहीं, अटकलें हैं कि अमेठी लोकसभा सीट से रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़ सकते हैं। एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, "अगर मैं सांसद बनने का फैसला करता हूं तो अमेठी के लोग मुझसे अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने की उम्मीद करते हैं।"

मुश्किल में सुनीता केजरीवाल! सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी कोर्ट की रिकॉर्डिंग, अब शिकायत दर्ज

▪ आधी आबादी डेस्क

आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल, उन्होंने 28 मार्च की कोर्ट प्रक्रिया की वीडियो/ऑडियो रिकार्डिंग सोशल मीडिया पर साझा की थी। इसको लेकर हाई कोर्ट के अधिवक्ता वैभव सिंह ने तीस हजारी कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश से संबंध में शिकायत दी है।

सुनीता केजरीवाल के साथ ही पार्षद प्रोमिला गुप्ता समेत अन्य के खिलाफ भी शिकायत दी है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आप नेताओं के साथ ही अन्य विपक्षी दलों ने भी जानबूझकर वीडियो-ऑडियो साझा किया, ताकि कोर्ट प्रक्रिया को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा सके। यह शिकायत राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बवेजा की 28 मार्च की कोर्ट प्रक्रिया को सोशल मीडिया पर साझा करने को लेकर दर्ज की गई है।

इस बीच यह बहस भी शुरू हो गई है कि क्या आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की जगह उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल दिल्ली की सीएम होंगी? इसका जवाब तो पार्टी के बड़े नेता और मंत्री सीधे तौर पर नहीं दे रहे हैं लेकिन उन्होंने यह जरूर साफ कर दिया है कि उनकी आप में बड़ी भूमिका होगी। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सुनीता केजरीवाल मौजूदा परिस्थिति में पार्टी को एकजुट रखने के लिए सही व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि सुनीता केजरीवाल की मौजूदगी का पार्टी काडर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सुनीता केजरीवाल ने हमेशा कहा है कि वह दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मेसेंजर हैं. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पार्टी की राजनीति न केवल इसके मेनिफेस्टो के इर्द-गिर्द घूमती है बल्कि सपोर्ट बेस, काडर और टॉप लीडरशिप के बीच का कनेक्शन भी संगठन को साथ रखने में अहम भूमिका निभाता है। सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से उनकी पत्नी की राजनीति में सक्रियता बढ़ गई है। वह लगातार सीएम केजरीवाल का संदेश वीडियो के जरिए लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही हैं तो साथ ही उन्हें इंडिया गठबंधन की रैली में भी देखा गया था जहां उन्होंने आम आदमी पार्टी की छह गारंटी पढ़कर सुनाई थी। उनकी सक्रियता को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि उन्हें सीएम केजरीवाल उन्हें कमान सौंप सकते हैं। हालांकि आप इस पर कुछ भी कहने से बचती नजर आ रही है। सीएम केजरीवाल को 21 मार्च को आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किया गया था। वह 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में है। उन्हें फिलहाल तिहाड़ जेल में रखा गया है। उन्हें पत्नी और बच्चों से मिलने की इजाजत दी गई है तो वहीं उनके वकील उनसे नियमित रूप से मुलाकात भी कर रहे हैं। गौरतलब है कि आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह छह महीने बाद बुधवार शाम क जेल से रिहा हो गए हैं। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने तिहाड़ के बाह कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, इसके बाद वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे, जहां उन्होंने सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। पिछले दिनों की कई हलचल बता रही है कि पार्टी में सुनीता केजरिवाल का कद लगातार बढ़ रहा है। जानकार मानते हैं कि अरबिंद केजरिवाल की गिरफ़्तारी ने पार्टी को मजबूत करने का काम किया है।

सर्राफा बाज़ार

22 कैरेट सोना	चांदी
₹62,580	₹80,800
प्रति 10 ग्राम	प्रति किलो

भारत के पहले आम चुनाव 1951-52 की कहानी, जब महिलायें नहीं बताती थीं अपना नाम!

▪ आधी आबादी डेस्क

15 अगस्त 1947 को भारत एक आजाद मुल्क बना। बावजूद इसके साल 1951 तक जब तक देश में पहला आम चुनाव नहीं हुआ तब तक यहाँ किंग जॉर्ज 11 के अधीन संवैधानिक राजतन्त्र था और लॉर्ड माउंट बेटन इसके गवर्नल जर्नल बने।

डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद के राष्ट्रपति बन जाने और उसी साल 15 दिसंबर 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के निधन के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के सबसे बड़े नेता बन गए थे। उस समय की भारत की राजनीति में कांग्रेस का बोलबाला था, हालांकि उसी दौरान आचार्य कृपलानी ने कांग्रेस से अलग होकर किसान मज़दूर प्रजा पार्टी बना ली थी। मतदाताओं के बीच कम्युनिस्ट पार्टी की एक सीमित लोकप्रियता थी और नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफ़ा देकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नई पार्टी जनसंघ बनाई थी। नए आज़ाद हुए देश ने कुछ सालों के भीतर ही वयस्क मताधिकार के आधार पर आम चुनाव करवाने का फ़ैसला किया। आज़ाद होने के दो वर्षों के भीतर भारत में चुनाव आयोग की स्थापना हो गई थी और मार्च, 1950 में सुकुमार सेन को पहला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था।

मतदाता सूची में महिलाओं का नाम जोड़ना समस्या बना

भारत के पहले आम चुनाव में करीब 17 करोड़ लोगों ने भाग लिया था जिसमें 85 फ़ीसदी लोग लिख पढ़ नहीं सकते थे। कुल मिलाकर करीब 4500 सीटों के लिए चुनाव हुआ था जिसमें 499 सीटें लोकसभा की थीं।

रामचंद्र गुहा अपनी किताब 'इंडिया आफ़्टर गांधी' में लिखते हैं, "पूरे भारत में कुल 2 लाख 24 हज़ार मतदान केंद्र बनाए गए थे। इसके अलावा लोहे की 20 लाख मतपेटियाँ बनाई गई थीं जिसके लिए 8200 टन इस्पात का इस्तेमाल किया गया था। कुल 16500 लोगों को मतदाता सूची बनाने के लिए छह महीने के अनुबंध पर रखा गया था।"

"उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी महिला मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ना। बहुत सी महिलाओं को अपना नाम बताने में झिझक थी। वो अपने आप को किसी की बेटी या किसी की पत्नी कहलाना अधिक पसंद करती थीं। चुनाव आयोग का प्रयास था कि हर मतदाता का नाम मतदाता सूची में लिखा जाए।" "इसका परिणाम ये हुआ कि करीब 80 लाख महिलाओं का नाम मतदाता सूची में नहीं लिखा जा सका। चुनाव करवाने के लिए करीब 56000 लोगों को प्रेसाइडिंग आफ़िसर के तौर पर चुना गया था। उनकी मदद के लिए 2 लाख 28 हज़ार सहायकों और 2 लाख 24 हज़ार पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था।"

कुछ दुर्गम पहाड़ी इलाकों में मतपेटियाँ पहुंचाने के लिए ख़ासतौर से पुलों का निर्माण किया गया था और हिंद महासागर के कुछ द्वीपों में मतदाता सूची पहुंचाने के लिए नौसैनिक पोतों का इस्तेमाल किया गया था। पश्चिमी देशों के अधिकतर मतदाता उम्मीदवार को उसके नाम से पहचान सकते थे लेकिन भारत में अधिकतर लोगों के अशिक्षित होने के कारण मतपत्र में मतदाताओं के नाम के आगे चुनाव चिन्ह छापा गया था। हर मतदान केंद्र पर मतपेटियाँ रखी रहती थीं जिस पर पार्टी का चुनाव चिन्ह बना होता था और मतदाताओं को उसमें अपना मत डालना पड़ता था। नकली मतदाताओं से बचने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐसी स्याही बनाई थी जो मतदाता की उंगली पर एक सप्ताह के लिए बनी रहती थी। भारत भर के 3000 सिनेमाघरों में चुनाव और मतदाताओं के अधिकार से संबंधित वृत्त चित्र दिखाया गया था। 1952 के चुनाव का पहला वोट 25 अक्तूबर, 1951 को हिमाचल प्रदेश की चीनी तहसील में डाला गया। उसी दिन ब्रिटेन में भी मतदान शुरू हुआ। अगले दिन ही चुनाव परिणाम आ गए और सत्ताधारी लेबर पार्टी को हरा कर कंज़रवेटिव पार्टी के विंस्टन चर्चिल एक बार फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन यहाँ के मतदाताओं को चुनाव परिणाम के लिए महीनों इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि देश के दूसरे भागों में जनवरी और फ़रवरी, 1952 में ही मतदान कराया जा सका।

आउटडेटेड है सरोगेसी पर बनी ये 'दुकान', मोनिका पंवार के अभिनय ने साधी कमजोर फिल्म

▪ स्मिता श्रीवास्तव

सरोगेसी यानी किराए की कोख। इस विषय पर आई कृति सैनन अभिनीत फिल्म मिमी भी एक लड़की की कहानी थी, जो पैसों की खातिर मां बनती है। हालात के चलते वह अपने बच्चे को खुद पालने का निर्णय लेती है। अब लेखक जोड़ी सिद्धार्थ और गरिमा ने भी इसी विषय को उठाया है। बतौर निर्देशक यह उनकी पहली फिल्म है। वह इसके लेखक और निर्माता भी हैं। उनकी यह 'दुकान' सरोगसी की है। माता-पिता बनने के सुख से वंचित लोगों के लिए उम्मीदों की दुकान है। सरोगेट मां को इसके बदले ढाई से तीन लाख रुपये मिलते हैं। साथ ही उनकी सुख-सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाता था। इतना पैसा शायद ही इन औरतों के पति कमा सकें।

क्या है दुकान की कहानी?

सरोगसी के जरिए मां बनने जा रही ऐसे ही कई महिलाओं की बातचीत से फिल्म शुरू होती है। दीया (मोनाली ठाकुर) और उसका पति अरमान (सोहम मजूमदार) पुलिस में जैस्मीन (मोनिका पंवार) के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हैं, जो सरोगेसी से उन्हें बच्चा देने वाली होती है। इस गांव में सरोगेसी क्लीनिक सरेआम चल रहे हैं, पर पुलिकर्मी की अनभिज्ञता पहले ही सीन में चौंकाती है। वहां से जैस्मीन की जिंदगी की परतें खुलनी शुरू होती हैं। पिता के अपनी बेटियों के साथ संबंध अच्छे नहीं होते। छुरी जैसी जुबान और दिल में समाज कल्याण रखने वाली 17 साल की जैस्मीन अपने से दोगुने आदमी सुमेर (सिकंदर खेर) से शादी करती है, जिसकी पहले से एक बेटी है। जैस्मीन बच्चा नहीं चाहती। अनिच्छा के बावजूद मां बनती है। अचानक से आए भूकंप में उसकी जिंदगी बदल जाती है। पति का निधन हो जाता है। बेटी की शादी के लिए जैस्मीन सरोगेट मां बनना तय करती है, ताकि दहेज के पैसों का इंतजाम कर सके। उसके बाद दीया के आग्रह पर वह सरोगेट मां बनती हैं। बच्चों से प्यार ना करने वाली जैस्मीन को इस बच्चे से प्यार हो जाता है। वह भाग जाती है। चार साल बाद जैस्मीन को पुलिस पकड़ने में कामयाब रहती है। जेल से वापसी के बाद वह बेटे की वापसी को लेकर लड़ाई लड़ती है।

आउटडेटेड है ये दुकान, कमजोर स्क्रीनप्ले

अब सरोगेसी को लेकर कानूनों में बदलाव हो चुका है, लेकिन यह फिल्म उस समय की है, जब सरोगेसी का धंधा खूब फलफूल रहा था। सिद्धार्थ और गरिमा ने विषय अच्छा चुना है, लेकिन वे ना तो कहानी, ना ही सरोगेसी की दुनिया को समुचित तरीके से चित्रित कर पाए हैं। सत्य घटना से प्रेरित होने के बावजूद फिल्म बनावटी ज्यादा लगती है। फिल्म की शुरुआत बहुत धीमे तरीके से होती है। गांव में सरोगेसी धड़ल्ले से होने के बावजूद वहां के लोग इससे अनभिज्ञ हैं। यह अपच है। सरोगेसी से मां बनने वाली किसी प्रकार की दिक्कतों को फिल्म नहीं दिखाती। ना ही उनकी निजी जिंदगी में जाती है। फिल्म में पूरी तरह से जैस्मीन छायी है। बाकी किरदारों की जिंदगी को फिल्म बिल्कुल नहीं छूती। सरोगेसी करने वाली महिलाओं का पक्ष बहुत सतही दिखाया है। सरोगेसी औरतों को लेकर दिखाया है कि वे खुश हैं। उन्हें होने वाले बच्चे से कोई लगाव नहीं है। आखिर में यह जैस्मीन के जरिए सरोगेट माओं और उनके माता-पिता की लड़ाई बन जाती है, जो अपने जने बच्चों को देखना चाहती है। बीच में जैस्मीन का लिव-इन भी दिखाया है, जो गायब हो जाता है। फिल्म देखते हुए सरोगेट मांओं का पेट बहुत ही बनावटी लगता है। फिल्म का स्क्रीनप्ले बेहद कमजोर है। संवाद भी महिलाओं की भावनाओं को पूरी तरह उकेर नहीं पाते हैं।

मोनिका पंवार ने संभाला अभिनय का मोर्चा

वेब सीरीज जामताड़ा: सबका नंबर आएगा से लोकप्रिय हुईं मोनिका पंवार के कंधों पर फिल्म की जिम्मेदारी है। उन्होंने जैस्मीन के अल्हड़पन, मस्तमौला स्वभाव और बेफ्रिकी को शिद्दत से जीया है। दिक्कत है कमजोर स्क्रीनप्ले और निर्देशन की। फिल्म में एक दृश्य में सनी देओल मेहमान भूमिका में सरोगेट मां को सम्मान देने की बात करते हैं। यह सीन जबरन ठूंसा हुआ लगता है। मोनाली ठाकुर पात्र को निभाते हुए संघर्ष करती नजर आती हैं। उन्हें गायिकी पर ही फोकस करना चाहिए। हिमानी शिवपुरी मां की भूमिका में जरूर प्रभावित करती हैं। फिल्म का बैकग्रांउड संगीत गुजराती पृष्ठभूमि के अनुरुप है। हालांकि, फिल्म की आतंरिक बुनावट और प्रस्तुति की कमी से गीत-संगीत की विशेषता दब गई है। दुकान में निश्चित रूप से एक सामाजिक संदेश है, लेकिन विषय को लेकर गहराई की कमी और गुणवत्ता उसे कमजोर बनाती है।

मूवी: दुकान
रेटिंग: ** (दो स्टार)
कलाकार: मोनिका पंवार, सिकंदर खेर, मोनाली ठाकुर, हिमानी शिवपुरी
लेखक व निर्देशक: सिद्धार्थ और गरिमा
निर्माता: एस के अहलूवालिया

प्रबंध संपादक: दिनेश के सिंह ❁ संपादक: हीरेन्द्र झा ❁ सलाहकार संपादक: चारुल मल्लिक, राजेश शर्मा, गीता सिंह ❁ डिज़ाइनर: मो. हसमतुल्लाह अंसारी

RNI-DELHIN/2013/51353